श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, आपकी बात हमारी सिर आंखों पर है। आप हमारा निवेदन सुन लीजिए। आपने यह कहा कि यह मामला यहां का नहीं है, राज्य अधिकार का है। हरिजनों की जमीन छीनी जा रही और माइनोरिटीज और हरिजनों पर जो अत्याचार हुए है, उनपर हाऊस में बहस हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक बात यह समझ लीजिए कि बहस जनरल टोपिक पर होती है। स्पेसीफिक मामले को लेकर अगर अतिक्रमण करना चाहेंगे, तो नहीं कर पाएंगे।

This is a specific case, no doubt.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जब बेलची में मर्डर हुई, तो वह मामला यहां पर उठाया गया था और जब उत्तर प्रदेश में मामला हुआ, तो वह उठाया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैं एलाऊ कर रहा हूं। अगर आप होने न दें, तो मैं क्या कर सकता हूं। We are having a discussion on this.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I cannot allow it because it is not a Central subject. मैंने रोका कब है लेकिन एक स्पेसीफिक सबजेक्ट को लेकर आप यहां पर बहस नहीं कर सकते।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हम एजोर्नमेंट मोशन दे रहे हैं और इस इशू पर पहले भी एजोर्नमेंट मोशन इस सदन में मंजूर हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रोका कब है। ...(व्यवधान)...**

MR. SPEAKER : He is unnecessarily doing it. Not a single word of what he has said will go on record. I have not allowed it.

(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : सारा कानून अपने हाथ में ले लिया है।

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : No, I will not allow it. He is going at full speed like the Rajadhani Express.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I am not a stooge. I am the Speaker. I must have the rights of the Speaker.

यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान) ..

गलत किया है। अगर ऐसा किया है, तो बुरा किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। व्यवस्था का एक ढंग होता है और अगर आप नहीं चलने देते हैं, तो दूसरी बात है। Why should we do it ? What will the general public think of what we are doing here ?

12.20 hrs.

LIFE INSURANCE CORPORATION BILL

Extension of time for presentation of Report of Joint Committee

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : I beg to move :

"That this House do further extend upto 14th August, 1984, the time

** Not recorded.

[Shri Mool Chand Daga]

for presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide, with a view to the more effective realisation of the objectives of nationalisation of life insurance business, for the dissolution of the Life Insurance Corporation of India and for the establishment of a number of corporations for the more efficient carrying on of the said business and for matters connected therewith or incidental thereto."

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : और कितना समय आप लेंगे ? उसको भी अभी पास कर देंगे ।

SHRI MOOL CHAND DAGA : I do not require any further time. I will present my report by that time.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : I suggest more time should be given to them.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) । माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी दफा डागा जी सदन के सामने आ रहे हैं कि इस समिति का समय बढ़ाया जाए । पहले स्वयं डागा जी ने इस तरह के प्रस्ताव का स्वयं विरोध किया था । मैं चाहता हूं कि डागा जी एक ही दफा इतना समय ले लें जिससे कि समिति की अच्छी तरह से रिपोर्ट आ सके । बार-बार समय बढ़ाने से तो आपकी साख भी गिरती है क्योंकि इस तरह के प्रस्ताव का आपने स्वयं ही इस सदन में विरोध किया है । आप एक बार ही पूरा समय ले लें, बार-बार आप समय न लें ।

श्री मूल चन्द डागा । माननीय अध्यक्ष जी, हमारी ड्राफ्ट रिपोर्ट को एप्रूव करते समय अगर हमारे माननीय सदस्य कोई डिसेन्टिंग नोट कर देंगे तो उसके लिए भी समय चाहिए । हमारे पास 700 मेमोरेण्डम आये थे, उनको और बाद में विटनेसिज को हमने एग्जामिन किया है ।

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House do further extend upto 14th August, 1984, the time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide, with a view to the more effective realisation of the objectives of nationalisation of life insurance business, for the dissolution of the Life Insurance Corporation of India and for the establishment of a number of corporations for the more efficient carrying on of the said business and for matters connected therewith or incidental thereto."

The Motion was adopted.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat) : Mr. Speaker, Sir, I did not want to come in the way of this Motion for extending the time of the Committee. It is all right, the House has approved it. I only want to bring it to your notice—and if necessary I will have to raise it formally—and I am sorry to have to say that the Chairman of this Joint Select Committee has gone on record through Press Statements making comments about the evidence which have been tendered in front of the Committee publicly, though they are supposed to be private. And I don't think it is in keeping with the functions of the Chairman.

MR. SPEAKER : No, it should not come in the Press.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Sir, I will have to move a Motion of privilege against him.

MR. SPEAKER : No, he should not.

SHRI MOOL CHAND DAGA : I have not made any statement before the Press. I have already contradicted it. It is a wrong thing. I deny it.

SHRI INDRAJIT GUPTA : He said that all the people are in favour of the Bill but only the trade unions are opposed to it. Is it the job of the Chairman to go about saying these things ?

MR. SPEAKER : It was brought to my notice earlier also by Shri Sunil Maitra.

SHRI INDRAJIT GUPTA : He is transgressing the powers of the Chairman of the Select Committee.

MR SPEAKER : I must be on record that nothing should go in the Press before the final Report.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Sir, I have denied it many times.

12.25 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need for early payment of pending D.A. instalments to Central Government Employees

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की चार किश्तें, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 अप्रैल तथा 1 मई 1984 से देय हैं। जिन के भुगतान में आवश्यक विलंब हो रहा है।

अप्रैल के बाद भी महंगाई लगातार बढ़ रही है। कोई भी आवश्यक वस्तु ऐसी नहीं है जिसके मूल्य में वृद्धि नहीं हुई हो। प्रेस ट्रस्ट के समाचार के अनुसार सभी वस्तुओं के लिये (1970-71 को आधार आंकड़ा 100 माना जाये) सरकारी थोक मूल्य सूचकांक पिछले हफ्ते के 336.0 (अस्थायी) की तुलना में अब बढ़ कर 338.0 (अस्थायी) हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि, सभी वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 35 लाख सरकारी कर्मचारियों के महगाई भत्ते की बकाया राशि का और किस्त बकाया पड़ गया है।

ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों में असंतोष का होना स्वाभाविक है। कर्मचारी महीनों से घोषित चार किस्तों की बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर महीनों से आंदोलन चला रहे हैं। 24 अप्रैल को वे वित्त मंत्री के निवास स्थान तथा देश के सभी प्रमुख नगरों में सामूहिक प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी 31 जुलाई, 1984 को केन्द्रीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर तमाम केन्द्रीय कर्मचारी वेतन बहिष्कार दिवस मनाने जा रहे हैं। इनका आंदोलन आगे भी बढ़ सकता है।

अतः भारत सरकार के वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि वह महंगाई भत्ते का बकाया चार किश्तों के नगद भुगतान की घोषणा कर उनके असंतोष को दूर करें।

(ii) Need for clearing the projects for increasing the storage capacity of D.V.C. to avoid floods in Hoogly and Howrah districts of West Bengal.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Every year, during the rainy season, the people of lower Bengal particularly the districts of Hoogly and Howrah are exposed to great hardships due to flood and water logging caused by the discharge of excess waters from reservoirs of Maithan and Panchet dams of the Damodar Valley Corporation. It is because the master plan to eliminate floods from the Damodar Valley has only been partially implemented.

Mr. W.L. Voorduin of the Tennessee Valley Corporation who had prepared the the DVC master plan, envisaged the construction of a total of seven multi-purpose